राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1799/2024

सीताराम माली **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं बागवानी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, पंत कृषि भवन, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.05.2024
आदेश की दिनांक : 24.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिषेक बी. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि संशोधित सूची दिनांक 22.01.2024 में अपीलार्थी का नाम भी जोडा जावे और अपीलार्थी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कृषि पर्यवेक्षक के पद पर हुई थी। उनका कथन है कि विभाग द्वारा दिनांक 19.12.2007 को झूठी विभागीय जांच अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिक के विरूद्ध प्रारंभ की गई और आदेश दिनांक 30.03.2015 के द्वारा अपीलार्थी व अन्य कार्मिकों को भी दोषमुक्त कर दिया गया और आदेश दिनांक 22.06.2015 के द्वारा दोषमुक्त रिपोर्ट परीक्षण के लिये कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि द्वारा दिनांक 18.12.2015 के द्वारा प्रमाणित हेतु भेजी गई और उक्त अधिकारी भी उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट हुये। तत्पश्चात् कार्यालय आयुक्त से प्रमुख शासन सचिव को दिनांक 09.03.2016 को

भेजी गई और क्रमशः उच्च अधिकारियों स्तर तक एवं मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक परीक्षण किया गया और आदेश दिनांक 18.01.2018 के द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.03.2020 के द्वारा अपीलार्थी व अन्य कार्मिकों को दण्डित करते हुये अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया। उनका कथन है कि परिनिंदा का दण्ड लघुदण्ड है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में पुनरावलोकन याचिका प्रस्तुत की है। अपीलार्थी की सेवा 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 11.07.2022 जारी किया गया, जिसमें 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एसीपी का लाभ दिया जाना दिनांक 23.09.2011 से बताया गया है और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.08.2022 के द्वारा जिसमें 27 वर्षीय एसीपी का लाभ दिनांक 23.09.2020 के बजाय 23.09.2021 से दिया जाना बताया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। जबकि अपीलार्थी को मात्र परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया है और अपीलार्थी को दिनांक 23.09.2011 एवं 30.09.2011 से दिया जाना स्वीकार किया गया और अब उसे दिनांक 23.09.2012 एवं 30.09.2012 से दिया जायेगा, जो एक वर्ष बाद विलम्ब से मिलेगा। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.08.2023 जिसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15170/2023 एवं 15002/2023 प्रस्तुत की गई, जो आज दिनांक तक लंबित है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.12.2022 जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि कार्मिक को लघु दण्ड दिया गया है तो उसकी एसीपी पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम में कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ पर्यवेक्षक का पद सृजित किया गया और पदोन्नति हेतु पात्रता रखने वालों की सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 250 पर अंकित किया गया और आदेश दिनांक 22.01.2024 के द्वारा जो कार्मिक पदोन्नत किये गये उनकी सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं दर्शाया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पद से वंचित रखा गया। दिनांक 01.02.2024 संशोधित सूची जारी की गई, जिसमें भी अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के समान अभ्यर्थी श्री मथुरा प्रसाद शर्मा एवं मीया राम मीणा जिनको भी अपीलार्थी के साथ दण्डित किया गया था, परंतु उन्हें विगत तिथि से पदोन्नति दी गई, जो सहायक कृषि

अधिकारी है और अपीलार्थी अभी–भी कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपनाया गया रवैया नियम एवं विधि के विपरीत है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, परंतु कोई विचार नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3128/2024 प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 08.05.2024 के द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हेतु निर्देश देते हुये निस्तारित की, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि संशोधित सूची दिनांक 22.01.2024 में अपीलार्थी का नाम भी जोडा जावे और अपीलार्थी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.03.2020 के द्वारा परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया था और 27 वर्षीय एसीपी का लाभ दिनांक 23.09.2020 के बजाय दिनांक 23.09.2021 से स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी को सीसीए नियम 18 के अंतर्गत परिनिंदा का दण्ड दिया गया है। परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक की वर्ष 2022–23 की पदोन्नति सूची दिनांक 22.01.2024 जारी की गई और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.03.2020 के द्वारा परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया था। अतः नियमानुसार उक्त दण्ड के प्रभाव के कारण वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक की वर्ष 2022–23 की पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया। श्री मथुरा प्रसाद शर्मा को दण्डादेश दिनांक 04.03.2020 के क्रम में वर्ष 2020–21 की कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी की पदोन्नति में उक्त दण्ड का प्रभाव डालते हुये एनएफएस किया गया तथा इनके एक वर्ष पश्चात् वर्ष 2021–22 की सहायक कृषि अधिकारी की डीपीसी में पदोन्नत किया गया। मथुरा प्रसाद शर्मा वर्ष 1980 भर्ती बैच के कृषि पर्यवेक्षक है जबकि अपीलार्थी वर्ष 1993 के बैंच के हैं। श्री मीया राम मीणा कृषि पर्यवेक्षक का पदोन्नति एवं एसीपी प्रकरण पुनः परीक्षण करवाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है और इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया आदेश नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कृषि पर्यवेक्षक के पद पर हुई थी। विभाग द्वारा दिनांक 19.12.2007 को झूठी विभागीय जांच अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिक के विरूद्ध प्रारंभ की गई और आदेश दिनांक 30.03.2015 के द्वारा अपीलार्थी व अन्य कार्मिकों को भी दोषमुक्त कर दिया गया और आदेश दिनांक 22.06.2015 के द्वारा दोषमुक्त रिपोर्ट परीक्षण के लिये कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि द्वारा दिनांक 18.12.2015 के द्वारा प्रमाणित हेतु भेजी गई और उक्त अधिकारी भी उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट हुये। तत्पश्चात् कार्यालय आयुक्त से प्रमुख शासन सचिव को दिनांक 09.03.2016 को भेजी गई और क्रमशः उच्च अधिकारियों स्तर तक एवं मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक परीक्षण किया गया और आदेश दिनांक 18.01.2018 के द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.03.2020 के द्वारा अपीलार्थी व अन्य कार्मिकों को दण्डित करते हुये अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया। परिनिंदा का दण्ड लघुदण्ड है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में पुनरावलोकन याचिका प्रस्तुत की है। अपीलार्थी की सेवा 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 11.07.2022 जारी किया गया, जिसमें 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एसीपी का लाभ दिया जाना दिनांक 23.09.2011 से बताया गया है और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.08.2022 के द्वारा जिसमें 27 वर्षीय एसीपी का लाभ दिनांक 23.09.2020 के बजाय 23.09.2021 से दिया जाना बताया गया है। जहां तक आलोच्य आदेश दिनांक 08.05.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर दण्डादेश दिनांक 04.03.2020 के क्रम में विभाग द्वारा जारी पदोन्नति सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को दण्डादेश दिनांक 04.03.2020 के द्वारा परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया था। परंतु यह भी सही है कि परिनिंदा का दण्ड एक लघुदण्ड की श्रेणी में आता है और इस प्रकार अपीलार्थी को लघु दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी को मिलने वाली देये तिथी से एसीपी का लाभ एक वर्ष आगे बढाकर दिया गया है, परंतु लघु दण्ड के द्वारा किसी कार्मिक की पदोन्नति को रोका जाना उचित प्रकट नहीं होता है। ऐसे मामले में माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :—

> *"39. In view of the discussions made above, this Court safely can held that withholding promotion for a Government servant on account of imposition of penalty of 'Censure' or 'withholding increment' is illegal and arbitrary and unconstitutional and therefore the Circular issued by the respondent- State in this regard disasters to be set aside." 40. In the case of Guman Singh Vs. State of Rajasthan & Ors. [(1971) 2 SCC 452], the Hon'ble Supreme Court has held that the Government cannot amend or supersede the statutory Rules by administrative instructions and any Circular containing the provisions for making the system so rigid that it curtail or restrict the powers conferred on the Selection Committee and Appointing Authority by the Rules. The Court further opined that such circulars/administrative instructions is per se opposed to the selection procedure envisaged under the Rules:- "The Apex Court made following observations in Para 39 of the verdict:*
>
> *39. Then the question is whether Government is competent to issue the said Circular and whether the Circular in any manner affects the discretion and powers of the Committee functioning under the statutory rules. The position is clear, as laid down by this Court in Sant Ram Sharma v. State of Rajasthan & Anr. (supra)*
>
> *"It is true that the Government cannot amend or supersede statutory rules by administrative instructions, but if the rules are silent on any particular point Government can fill up the gaps and supplement the rules and issue instructions not inconsistent with the rules already framed."*
>
> *The Court further proceeded to observe on evaluation of the Circular, in Para 47, as under:*
>
> *47. One gets a fairly good picture of the nature of the instructions contained in the circular issued by the Government. No doubt a properly evaluated marking system may be helpful for assessing the merit of persons who are already in service. But the instructions given in the circular are so rigid that they are opposed to the selection to be made strictly on merit as provided under Rules 28-B and 32.*
>
> *While appreciating the object of the Circular, the Apex Court proceeded to observe that such a circular offend the Rules, in Para 53 of the verdict:*
>
> *53. The object of the circular may be to bring about uniformity in the award of marks. But the directions contained therein do offend the rules. This is not a case of the Government filling up the gaps or of giving executive instructions on matters not provided for by or not inconsistent with the rules. The Learned Judges of the Division Bench of the High Court, have by and large, upheld the validity of the marking system as well as the other instructions contained in the circular of 1966 on the ground that the marking system as pointed out by the State has been in vogue from 1960, on the basis*

of a previous circular, dated August 31, 1960, issued by the State Government. Reliance placed upon this circular of 1960 by the High Court, in our opinion, is not justified. We have gone through the circular of 1960 which is No.F.1(6)Apptts.(D)/60, dated August 31, 1960. That circular was issued by the State to clarify the misapprehension that appears to have been caused in the application, for promotion on the principle of merit-cum seniority or seniority-cum merit. For the purpose of having uniformity, the State Government had laid down certain principles in the said circular to be borne in mind by the Promotion Committees. No doubt there is a marking system indicated therein. But there are two features which distinguish the circular of 1960 from that of the 1966 circular. In Paragraph 3 of the former circular, it is specifically laid down that the principles mentioned therein are only in the nature of executive instructions to be kept in view by the Committees when marking promotions. It is made clear that those Committees "should however, exercise their own discretion while applying the above principles in view of the fact that occasionally the Confidential Rolls may not have been written with full sense of responsibility. Moreover, some of the rules permit interview before selection and in such cases the Selection Committee will have to assess suitability of the officer as a result of the interview also". Under the circular of 1966, we have already indicated, no such discretion is left to the Selection or Promotion Committees to adopt any method other than that indicated in the circular. In fact, it is emphasised that the Statutory Service Rules and the instructions contained in the circular are to be treated as a complete code by the Committees. Another point to be noted is that in 1960 the question of promotion on the basis of merit alone had no place. That principle was adopted only, as pointed out by us earlier, in 1965 which led to the amendment of the rules. Therefore, the principles mentioned in the circular of 1960 cannot be relied on when considering the validity of the present circular, when promotion by merit alone has been recognized by the Rules from 1965. We have already indicated that the instructions in the 1966 circular contravene the Rules. Therefore, we are of the opinion that the circular, dated August 27, 1966, is bad and accordingly it is struck down. We make it clear that we express no opinion on the validity or otherwise of the circular of August 31, 1960. We have only referred to that circular to show that the High Court has committed an error in placing reliance on the same."

41. The Hon'ble Apex Court while reiterating the principles laid down in the Constitution Bench judgment in case of Guman Singh (supra) as held in case of Sarva U.P. Gramin Bank Vs. Manoj Kumar Chak [(2013) 6 SCC 287), has held as under:-

"43. We also do not find any merit in the submission of Mr. Dhruv Mehta that Circular No.17 of 2009 dated 30.11.2009 and Circular dated 12.7.2010 are to ensure that the individual members of DPC do not recommend for promotion an individual officer despite having been punished in the proceding five years. Such curtailment of the powers of DPC would have to be located in the statutory service rules. The 1998 Rules do not contain any such provision. The submission needs merely to be stated, to be rejected. We also do not find any merit in the submission of Mr. Mehta that without the aforesaid guidelines, an officer, even though, he has been punished for gross misconduct would have to be permitted to be promoted as no minimum

marks are prescribed for interview or performance appraisal. In our opinion, it is fallacious to presume that under the 1998 Rules, once an officer gets the minimum marks in the written examination, he would be entitled to be promoted on the basis of seniority alone. There is no warrant for such a presumption. The misconduct committed by an eligible employee/officer would be a matter for DPC to take into consideration at the time of performance appraisal. The past conduct of an employee can always be taken into consideration in adjudging the suitability of the officer for performing the duties of the higher post.

44. There is another very good reason for not accepting the submissions made by Mr. Dhruv Mehta. Different rules/regulations of the banks provide specific punishments such as "withholding of promotion, reduction in rank, lowering in ranks/pay scales". However, there is another range of penalty such as censure, reprimand, withholding of increments, etc. which are also prescribed under various staff regulations. To debar such an employee from being considered for promotion would tantamount to also inflicting on such employee, the punishment of withholding of promotion. In such circumstances, a punishment of censure/reprimand would, in fact, read as censure/reprimand plus five years' debarment from promotion. Thus the circulars issued by the Bank debarring such employees from being considered would be clearly contrary to the statutory rules. The circulars clearly do not fall within the ratio in Sant Ram case.

45. In our opinion, the observations made by this Court in Ram Ashish Dixit are a complete answer to the submissions made by the learned counsel for the appellants, Mr. Dhruv Mehta. Therefore the High Court, in our opinion, has rightly quashed the aforesaid two circulars and directed that the respondent beb considered for promotion in accordance with the applicable rules."

42. The Hon'ble Division Bench of this Court in case of State of Rajasthan & Ors. Vs. Ashok Singhvi D.B. Special Appeal (Writ) No. 232/2013, decided on 06.08.2013, after giving thoughtful consideration to the judgment of the Hon'ble Apex Court in case of State of Rajasthan & Ors. Vs. Shanker Lal Parmar (AIR 2012 SC 1913, Guman Singh (supra), held Sarva U.P. Gramin Bank (supra) has observed as under:-

"We have heard the learned counsel for the parties at length, scanned the materials on record and perused the impugned order passed by the learned Single Judge.

A glance at the impugned order passed by the learned Single Judge clearly and unequivocally reveals that the learned Single Judge has simply confined the relief to the respondent visa- vis his right of consideration for promotion and question of his suitability for promotion has been left open to be decided by the competent authority. Learned Single Judge has further observed that if the penalty suffered by the incumbent adversely effects minimum merit necessary for efficiency of administration, the DPC can adjudge him unsuitable for promotion. Learned writ Court has further concluded that debarring an incumbent from his right of consideration for promotion on the strength of Circular dated 26th of July 2006 is not

sustainable and that being so issued directions to consider the candidature of the respondent ignoring the said Circular. On examining the impugned order in the light of Rule 24A of the Rules of 1963 and on the touchstone of the Constitution Bench judgment of the Apex Court in Guman Singh's case (supra), and the latest verdict of the Hon'ble Apex Court in case of Sarva U.P. Gramin Bank's case (supra), we do not feel persuaded to interfere with the impugned order. The legal precedents which are cited by the learned Addl. Advocate General, are having no bearing whatsoever on the issue involved in the matter, and therefore, these judgments are of no help to the appellants. We, therefore, fully concur with the impugned order passed by the learned Single Judge and find no merit in this appeal."

43. The Co-ordinate Bench of this Court at Principal Seat Jodhpur in case of Jhhabar Singh Charan Vs. State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Writ Petition No. 7119/2022, decided on 10.05.2023 after relying on various judgments has observed as under:-

"8. In the present matter, it is not disputed that the criteria for promotion is seniority-cummerit and therefore, the ratio as laid down vide the above judgments would definitely apply. In the present petition, earlier, specific directions were issued to the respondent-Department and in pursuance to the same, result of DPC has been placed on record and as per the said result, the petitioner has been recommended for promotion.

9. In view of the settled proposition of law, the present writ petition is partly allowed. As the petitioner has already been recommended for promotion in the DPC, the orders qua his promotion be issued in terms of law within a period of one month from the date of receipt of the present order."

44. So considering the provisions of Rules and the law laid down in various judgments, as referred above, this Court can safely held that the Circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel to the extent of depriving the Government servants from consideration for promotion in case of criteria for promotion being Seniority-Cum-Merit on account of penalty of 'Censure' or withholding increments, is not sustainable and deserves to be set aside.

45. Accordingly, the present writ petition is allowed. The order of penalty dated 30.05.2013, passed by the Deputy Commissioner of Police, Jaipur, the order dated 27.12.2013 passed by the Commissioner of Police, Jaipur and also the order dated 26.10.2015 passed by the Joint Secretary Government of Rajasthan (Appeal) and so also the Circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel to the extent as observed in above paras, are quashed and set aside. The petitioner shall be entitled for all consequential benefits which accrue to him as if no such order of penalty was ever passed against him.

46. The exercise for promotion or review so as to extend the consequential benefits to the petitioner, be completed by the respondents within a period of three months from today.

47. In view of the order passed in the main petition, the stay application and pending application(s), if any, also stand disposed of."

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि परिनिंदा के दण्ड से दण्डित कार्मिक को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त प्रकरण के समान है और अपीलार्थी भी उक्त न्यायिक विनिश्चय के आधार पर पदोन्नति पाने का हकदार है। यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी कार्मिक को परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया है तो विभाग द्वारा पदोन्नति रोके जाने के संबंध में पृथक से आदेश जारी करना होता है। परंतु इस प्रकार का कोई आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 08.05.2024 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक विनिश्चय को ध्यान में रखते हुये सूची दिनांक 22.01.2024 में संशोधन करते हुये अपीलार्थी के नाम पर भी अंकन किया जावे तथा उक्त परिनिंदा के दण्ड के संबंध में अपीलार्थी की पदोन्नति को न रोकते हुये उसे वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य